अब सोनभद्र से हरिद्वार को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे : योगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की घोषणा की। प्रयागराज से मेरठ तक बनकर लगभग तैयार 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का अब सोनभद्र से हरिद्वार तक विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयागराज से आगे मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में शक्तिनगर तक विस्तार होगा। आगरा-लखनऊ-हरदोई-फर्रुखाबाद की गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए भी बजट में घोषणा हुई है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली, सोनभद्र के शक्तिनगर तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी ही निवेश का आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उप्र कभी 'बीमारू' की श्रेणी में गिना जाता था, आज वही देश की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है। उन्होंने इसे 'विकसित भारत-2047' की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं, निवेश विस्तार और रोजगार सृजन की नई पटकथा लिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ वर्षों में बिना नया टैक्स लगाए राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई योजनाएं और ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पूंजीगत व्यय प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को गति देगा।

बजट में स्टेट डाटा अथारिटी के गठन, डाटा सेंटर क्लस्टर, यूपी एआइ मिशन और साइबर सेक्योरिटी आपरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा को सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बता रही है। स्किल डेवलपमेंट हब, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना व स्टार्टअप पर इस बजट में जोर दिया गया है। आइआइटी कानपुर और आइआइटी बीएचयू के साथ 'डीप टेक' सहयोग के जरिये युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जाएंगे। डीप टेक उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग नवाचार पर आधारित तकनीक होती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 23 लाख डीजल पंपों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना घोषित की गई है। एससी-एसटी और महिला किसानों को 90 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रविधान किया गया है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए रिवाल्विंग फंड, एग्री एक्सपोर्ट हब और दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार अन्नदाता को उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिला उद्यमी उत्पाद एवं विपणन केंद्र (शी-मार्ट माडल), महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड और ब्याजमुक्त ऋण सुविधा की घोषणा बजट में की गई है। श्रमजीवी महिला छात्रावास और महिला गाइड के लाइसेंस शुल्क में छूट जैसे कदमों से महिला श्रमबल भागीदारी को और बढ़ाने का लक्ष्य है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट पर बोले मुख्यमंत्री

- इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को गति देगा ढाई लाख करोड़ का व्यय
- पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को विस्तार स्टेट डाटा अथारिटी का होगा गठन
- एआइ मिशन को देंगे रफ्तार, सुरक्षा कौशल और स्टार्टअप पर जोर

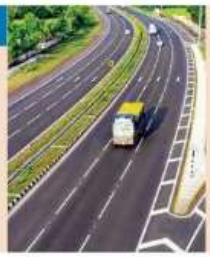

"यह बजट नए उत्तर प्रदेश की निर्णायक छलांग है। वर्ष 2029-30 में प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में रणनीतिक कदम है। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 2.24 प्रतिशत रह गई है।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री